भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 153

जिसका उत्तर 2 फ़रवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे परियोजना की प्रभावशीलता

153. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे परियोजना के अप्रभावी होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यक्रम के लागू होने के सात वर्षों के बाद कुल 759 परियोजनाओं में से केवल 224 (29.5 प्रतिशत) परियोजनाएं ही पूरी किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की सिफारिश को लागू करने का विचार है ताकि विवादों को सुलझाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ नमामि गंगे के संदर्भ में अंतर-राज्यीय संबंधों का आकलन किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडु)

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन बहुत प्रभावी रहा है और विशेष रूप से हाल ही में इसमें तेजी आई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट (घाट और श्मशान घाट विकास), ई-प्रवाह, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी आदि जैसे प्रभावी कार्य की शुरूआत की है। अभी तक, गंगा बेसिन राज्यों में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा कुल 409 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 232 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। दिसंबर 2022 तक उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

सीवेज अवसंरचना									
31 दिसंबर 2022 तक परियोजनाओं की स्थिति									
क्र सं	**राज्य**	**परियोजनाओं की संख्या**	**सृजित की जाने वाली एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)**	**पुराने एसटीपी के पुनरूद्धार के माध्यम से एसटीपी क्षमता का निर्माण (एमएलडी में)**	**बिछाई जाने वाली सीवेज नेटवर्क (किमी में)**	**पूर्ण परियोजनाओं की संख्या**	**सृजित की गई एसटीपी क्षमता**	**पुराने एसटीपी के पुनरूद्धार के माध्यम से सृजित की गई एसटीपी क्षमता एमएलडी में**	**बिछाई गई सीवर नेटवर्क (किमी में)**
1.	उत्तराखंड	41	223.14		196.23	33	164.50		169.61
2.	बिहार	33	676.10	0.00	1770.21	10	233.50	0.00	1160.40
3.	पश्चिम बंगाल	26	684.18	187.04	1030.43	1 1	137.03	137.04	841.87

उत्तराखंड में, स्थापित सीवेज उपचार क्षमता उत्पन्न सीवेज से अधिक है; जबकि बिहार में नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन होने से सीवेज उपचार क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में जनवरी 2022- दिसंबर 2022 के दौरान 260.74 एमएलडी क्षमता की उपचार क्षमता वाले 26 सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) वाली 16 सीवरेज परियोजनाएं पूरी की गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2022 (जनवरी से अक्टूबर) में गंगा नदी के मुख्य धारा वाले 5 राज्यों में पानी की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर, पाई गई पानी की गुणवत्ता से संकेत मिलता है कि घुलित ऑक्सीजन का औसत मूल्य, जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान के पानी की गुणवत्ता मानदंड की स्वीकार्य सीमा के भीतर और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग करने के की दृष्टि से उसे लिए संतोषजनक पाया गया है।

इसके अलावा, बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, पानी की गुणवत्ता के मापदंडों के औसत डेटा की तुलना के अनुसार, वर्ष 2014 और 2022 (जनवरी से अक्टूबर) के घुलित ऑक्सीजन (डीओ) और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) में; क्रमशः डीओ (मेडियन) ने 33 स्थानों पर, बीओडी (मेडियन) ने 40 स्थानों पर और एफसी (मेडियन) ने 28 स्थानों में सुधार किया है।

नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है तथा भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रही है। परियोजनाओं ने अब अपनी गति पकड़ ली है और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख): नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, कुल 409 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से 232 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो कुल स्वीकृत परियोजनाओं का 57% है।

बुनियादी अवसंरचना और सीवरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं में शामिल हैं: सड़क काटने के लिए अनुमति प्राप्त करने में देरी, रेलवे/एनएच क्रॉसिंग, भूमि खरीद, वन मंजूरी, स्थलों के परिवर्तन, कोविड-19, असामान्य बाढ़ आदि । हालांकि, इन मामलों का समाधान करने के लिए कदम उठाए गए हैं और परियोजना के पूरा होने में तेजी आई है। वर्ष 2022 (जनवरी-दिसंबर) में, 26 सीवरेज परियोजनाएं पूरी की गईं और लगभग 1,200 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण किया गया।

(ग) और (घ): एनएमसीजी की कार्यकारी समिति (ईसी) ने 13 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में "नमामि गंगे के लिए अंतरराज्यीय सहयोग: नीति और संस्थागत चुनौतियां और अवसर" पर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को 14 दिसंबर 2021 को सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के लिए एनएमसीजी और केंद्र के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के अनुसरण में विकसित किया गया था। प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. बेसिन में मतभेदों और सहयोग के इतिहास को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय संबंधों का आकलन करना।

ii. सामूहिक कार्रवाई को गति देने की क्षमता को समझने के लिए बेसिन में पानी की गुणवत्ता के बारे में उभरती हुई सामूहिक चिंताओं की जांच करना।

iii. गंगा कायाकल्प के लिए अंतरराज्यीय सहयोग को सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र के लिए कमियों और अवसर की पहचान करना।

*****